

एसोसिएटेड स्टोन इंडस्ट्रीज (कोटा) लिमिटेड

बनाम

आयकर आयुक्त, राजस्थान

5 फरवरी 1997

[बी.पी. जीवन रेड्डी और के.एस. परिपूर्णन, न्यायमूर्तिगण]

आयकर अधिनियम 1922 - धारा 34(1)(ए), 34(1)(बी) - पुनर्मूल्यांकन - आवश्यकताएँ-सामग्री का खुलासा करने के लिए निर्धारिती का कर्तव्य अधिनियम - निर्धारिती, एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी जो कोटा के महाराव द्वारा दिए गए पट्टे पर पत्थरों के उत्खनन का व्यवसाय करती है - पट्टा विलेख के संदर्भ में निर्धारिती द्वारा रॉयल्टी का भुगतान-इसके बाद, कोटा राज्य का विलय। राजस्थान राज्य - निर्धारिती, राजस्थान राज्य और भारत संघ के बीच कर लगाने के संबंध में जिला न्यायालय के समक्ष लंबित विवाद - भुगतान की गई अतिरिक्त रॉयल्टी की राशि, जिसे पहले कटौती के रूप में अनुमति दी गई थी, पुनर्मूल्यांकन पर अस्वीकृत - आयोजित, पुनर्मूल्यांकन- धारा 34(1)(ए) के तहत तत्काल मामले में शुरू की गई कार्यवाही अमान्य थी क्योंकि भौतिक तथ्यों का खुलासा करने में निर्धारिती की ओर से कोई विफलता नहीं थी-हालांकि धारा 34(एल)(बी) के तहत नोटिस जारी रखा जा सकता है और आगे बढ़ सकते हैं- , धारा 34(1)(ए) के तहत शुरू किए गए कार्यों को धारा-34(1)(बी) के तहत पूरा किया जा सकता है।

आयकर अधिनियम 1922 - धारा 180 ए - दंडात्मक ब्याज लगाना - के खिलाफ अपील - निर्धारण के आदेश के खिलाफ निर्धारिती द्वारा चुनौती दी जा सकती है- मामले को विचार के लिए उच्च न्यायालय में भेजा गया।

अपीलकर्ता, एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी की स्थापना 17 जनवरी, 1945 को तत्कालीन भारतीय राज्य कोटा में पत्थर उत्खनन का व्यवसाय करने के लिए की गई थी। कोटा राज्य के तत्कालीन महाराव ने 2 मई 1945 को एफ निर्धारिती कंपनी को 15 साल की अवधि के लिए पट्टा प्रदान किया था। अक्टूबर 1944 से। पट्टा समझौते के खंड 18 में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान किया गया है कि अनुदानकर्ता द्वारा दी गई रियायतों और विशेषाधिकारों पर विचार करते हुए और आयकर, सुपर-टैक्स और अतिरिक्त लाभ कर के बदले में, अनुदान प्राप्तकर्ता को अनुदानकर्ता को भुगतान करने के लिए अनुबंधित किया गया था। उत्खनित पत्थर पर रॉयल्टी एक रुपये प्रति 100 वर्ग फुट की दर से दी जाएगी, बशर्ते कि न्यूनतम राशि 1,50,000 रुपये प्रति वित्तीय वर्ष हो, जब तक कि बिना पॉलिश किए गए स्लैब की बिक्री दर प्रति 100 वर्ग फुट रुपये से अधिक न हो। इसके बाद, कोटा राज्य ने संयुक्त राज्य राजस्थान का विलय कर दिया और आयकर अधिनियम 1922 को 1 अप्रैल 1950 से नवगठित राजस्थान राज्य में लागू किया गया। निर्धारिती द्वारा दायर एक नागरिक मुकदमे पर जिला न्यायाधीश, कोटा की एक अदालत ने भारत संघ और राजस्थान राज्य के खिलाफ, यह घोषणा करने की मांग की कि उसे आयकर के भुगतान से छूट दी गई है कि उसके द्वारा न्यूनतम रुपये की राशि से अधिक भुगतान की गई रॉयल्टी 1,50,000 आय, कर, सुपर-टैक्स आदि के बदले में थे, जिला न्यायाधीश ने भारत संघ के खिलाफ मुकदमे को खारिज करते हुए कहा कि राजस्थान राज्य न्यूनतम रॉयल्टी राशि रुपये का हकदार था। 1,50,000 रुपये जबकि भारत संघ उस वर्ष भुगतान की गई अतिरिक्त रॉयल्टी में से संघीय करों के संबंध में निर्धारिती कंपनी की कर देयता के बराबर राशि का हकदार था और राजस्थान राज्य शेष का हकदार था। निर्धारण वर्ष 1950-51 से 1961-62 के लिए आयकर अधिकारी ने न्यूनतम रॉयल्टी राशि रुपये की कटौती को अस्वीकार कर दिया।

कटौती के रूप में भुगतान की गई अतिरिक्त रॉयल्टी की अनुमति देते हुए पूंजीगत व्यय के रूप में 1,50,000 वर्ष 1959 में, कर के पुनर्मूल्यांकन के लिए नोटिस आयकर अधिनियम के धारा 34(1)(ए) निर्धारण वर्ष 1950-51 से 1956-57 के लिए जारी किए गए थे और पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही में, भुगतान की गई अतिरिक्त रॉयल्टी की राशि, जिसे पहले अनुमति दी गई थी, को अस्वीकार कर दिया गया था। और निर्धारिती कंपनी की आय में वापस जोड़ा गया। निर्धारिती द्वारा अपील करने पर, अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा राशि की अस्वीकृति की पुष्टि की गई। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने निर्धारण वर्ष 1950-51 से 1961-62 के लिए अपने दो आदेशों द्वारा आयोजित किया:

(ए) कि उन वर्षों के संबंध में मूल्यांकन के लिए आवश्यक किसी भी प्रासंगिक सामग्री को पूरी तरह से और सही मायने में प्रकट करने में निर्धारिती कंपनी की ओर से कोई विफलता नहीं हुई है; (बी) मूल्यांकन वर्ष 1954-55 से 1956-57 के संबंध में, कार्यवाही हालांकि मूल मूल्यांकन की तारीख से चार साल की अवधि के भीतर शुरू की गई थी, फिर भी क्योंकि ऐसी कार्यवाही एस/धारा 34(1)(ए) के तहत शुरू की गई थी। अधिनियम की धारा के तहत बनाये जाने के कारण उन्हें बरकरार नहीं रखा जा सका। अधिनियम की धारा 34(1)(बी); (सी) कि राज्य सरकार को भुगतान की गई अतिरिक्त रॉयल्टी का हिस्सा जो निर्धारिती कंपनी की कर देनदारी के बराबर था, स्वीकार्य कटौती नहीं हो सकती है। हालांकि, भुगतान की गई अतिरिक्त रॉयल्टी का अवशेष के रूप में शेष भाग अनुमेय कटौती था; (डी) करदाताओं का मानना है कि कंपनी रॉयल्टी के उस हिस्से के क्रेडिट की हकदार थी जो उसने आयकर और सुपर टैक्स देनदारी के बदले में भुगतान किया था; और (ई) आकलन वर्ष 1957-58 से 1961-62 के लिए, राशि रु. न्यूनतम रॉयल्टी के रूप में भुगतान किया गया 1,50,000 राजस्व प्रकृति का व्यय और एक अनुमेय कटौती थी। यह भी कि केंद्र सरकार को आयकर, सुपर टैक्स आदि के बराबर राशि के भुगतान के बाद भुगतान की गई अतिरिक्त रॉयल्टी से बचा हुआ अवशेष राजस्व व्यय और एक अनुमेय विचलन था।

संदर्भ पर, उच्च न्यायालय ने माना कि:-

(i) वर्ष 1950-51 के लिए पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही 1956-57 को वैध रूप से शुरू किया गया और निष्कर्ष निकाला गया; (ii) वर्ष 1954-55, 1955-56 और 1956-57 के लिए पुनर्मूल्यांकन को धारा 34(1)(बी) के तहत उचित ठहराया जा सकता है; (iii) चुनौती धारा 18(6) या 18 ए(8) के तहत दंडात्मक ब्याज का आरोप केवल कर निर्धारण के आदेश के खिलाफ अपील में किया जा सकता है; और (iv) निर्धारिती कंपनी अतिरिक्त रॉयल्टी की किसी भी राशि के लिए क्रेडिट की हकदार नहीं थी, व्यय राजस्व प्रकृति का नहीं होने के कारण, स्वीकार्य कटौती नहीं हो सकती है। इसलिए यह अपील।

आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हुए,

इस न्यायालय ने आंशिक रूप से अपील स्वीकार किया

अभिनिर्णीत 1.1. आयकर अधिनियम 1922 की धारा 34(एल)(ए) के तहत मूल्यांकन वर्ष 1950-51 के लिए पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही अमान्य थी। उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की कि शुरू की गई उक्त पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही वैध थी। [962-एच]

1.2. अधिनियम की धारा 34(1)(ए) के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं। एक यह है कि आयकर अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि आय मूल्यांकन से बच गई है और दूसरी बात, उसके पास यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि इस तरह का पलायन रिटर्न करने या पूरी तरह से और वास्तव में

पुराने भौतिक तथ्यों का खुलासा करने के लिए चूक या विफलता के कारण था, यानी प्राथमिक तथ्य आवश्यक हैं प्रासंगिक वर्ष के लिए मूल्यांकन के लिए। प्रकट किए गए प्राथमिक तथ्यों से कौन से तथ्यात्मक कानूनी, या अन्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, इस पर आयकर अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने या आकर्षित करने के लिए निर्धारिती पर कोई कर्तव्य नहीं है। [968-ई-एफ]

1.3. इस मामले में प्राथमिक तथ्य अपीलकर्ता द्वारा 2 मई 1945 को कोटा राज्य के महाराव के साथ किया गया पट्टा समझौता है; जिसे मूल मूल्यांकन के समय आयकर अधिकारी के समक्ष रखा गया था। यह निर्धारिती का कर्तव्य नहीं है कि वह अधिकारी का ध्यान दस्तावेज के किसी विशेष खंड या हिस्से की ओर आकर्षित करे और उसे उससे कोई विशेष निष्कर्ष निकालने के लिए आमंत्रित करे। करदाता-कंपनी पर किसी भी आयकर का आकलन करने या लगाने से कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम निषेधाज्ञा आयकर अधिकारी की जानकारी में थी, जैसा कि मूल मूल्यांकन से देखा जा सकता है। इसके अलावा मुकदमे में, भारत संघ और आयकर आयुक्त ने लिखित बयान दायर किए थे। आयकर अधिकारी को त्रिकोणीय विवाद के बारे में पता था-एक सी-कंपनी, राजस्थान राज्य और भारत संघ जिला न्यायालय के समक्ष लंबित है। इसलिए यह स्पष्ट है कि इन वर्षों में मूल्यांकन के लिए आवश्यक प्राथमिक तथ्यों का खुलासा करने में निर्धारिती की ओर से कोई चूक नहीं हुई है। [970-बी-ई]

2.1 धारा 34 समग्र रूप से मूल्यांकन से बचने वाली आय बी को फिर से खोलने के मामलों से संबंधित है। जबकि धारा 34(1)(ए) के आधार पर आयकर अधिकारी द्वारा एक विश्वास के गठन की आवश्यकता होती है जो कुछ सामग्री के बारे में कि निर्धारिती की ओर से सभी भौतिक तथ्यों को पूरी तरह और सही मायने में प्रकट करने में विफलता या चूक हुई है; धारा 34(1)(बी) में प्रावधान है कि भले ही निर्धारिती की ओर से कोई चूक या विफलता नहीं हुई हो, लेकिन, यदि आयकर अधिकारी के पास यह विश्वास बनाने के लिए जानकारी है कि आय मूल्यांकन से बच गई है, तो वह चार साल की अवधि के भीतर कार्यवाही शुरू कर सकता है। धारा 34(1)(ए) अधिक कठिन और कठोर है जबकि धारा 34(1) (बी) मामलों के एक बड़े वर्ग को कवर करते हुए व्यापक महत्व का है। सामान्य नागरिक कार्यों की तरह, जहां एक पक्ष बड़ी राहत के लिए प्रार्थना करता है और न्यायालय मानता है कि वह इसके लिए हकदार नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है तथ्यों से सिद्ध या स्वीकार किया गया है कि पक्ष कम राहत का हकदार है, अदालत हमेशा राहत देने के लिए खुली है; इसी प्रकार यदि आयकर अधिकारी ने धारा 34(1)(ए) के कड़े और कठिन प्रावधानों के तहत कार्यवाही शुरू की है जो अमान्य पाया गया है, तो अपीलिय या अन्य उच्च प्राधिकारी को धारा 34(1)(बी) को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता है ई), यदि खंड (बी) की प्रयोज्यता के लिए पूर्व-अपेक्षित शर्तें संतुष्ट हैं। दूसरे शब्दों में, यदि धारा 34(1)(बी) की प्रयोज्यता की शर्तें जो केवल छोटी अवधि की सीमा प्रदान करती हैं, संतुष्ट हैं, तो धारा 34(1)(ए) के तहत शुरू किए गए मूल्यांकन को धारा के तहत बरकरार रखा जा सकता है या उचित ठहराया जा सकता है। अधिनियम की धारा 34(1)(बी). आयकर अधिकारी द्वारा प्राप्त जानकारी रिकॉर्ड से बाहर की होनी जरूरी नहीं है; यह पहले से उपलब्ध मूल्यांकन रिकॉर्ड से प्राप्त किया जा सकता है। [973-बी-ई]

आनंदजी हरिदास एंड कंपनी (पी) लिमिटेड बनाम एस. पी. कुशारे एसटीओ, एआईआर (1968) एससी 565 = (1968) 21 एसटीसी 326, अनुसरण किया।

2.2. यद्यपि तीन मूल्यांकन वर्षों 1954-55 से 1956-57 के लिए कार्यवाही

अधिनियम की धारा 34(1)(ए) के तहत कायम नहीं रखी जा सकती, उन्हें अधिनियम की धारा 34(1)(बी) के तहत कायम रखा जा सकता है, क्योंकि सामग्री – रिकॉर्ड पर खुलासा करें कि धारा 34(1)(बी) के तहत पूरी की जाने वाली आवश्यक शर्तें पूरी हो गई हैं। [975-ई]

रघुबर दयाल राम कृष्ण 'सी. आई. टी., (1967) 63 आईटीआर 572, अस्वीकृत हुआ।

मृगांका मोहन सूर बनाम सी.आई.टी., (1974) 95 आईटीआर 503; श्रीमती निमला बिड़ला बनाम डब्ल्यूटीओ, (1976) 105 आईटीआर 483 एफबी; गंगा सरन एंड संस (एचयूएफ) बनाम आईटीओ, (1981) 130 आईटीआर 212; राजबली हरजी मेघानी बनाम एस.एन. सहाने, (1988) आईटीओ आईटीआर 614; टी.एम. कौसाली बनाम छठा आईटीओ, (1985) 155 आईटीआर 739 (कर); सी.आई.टी. बनाम बनवारी लाल एंड संस लिमिटेड, (1982) 137 आईटीआर 91 (डेल); मैसूर टोबैको कंपनी लिमिटेड बनाम सी.आई. टी., (1986) 157 आईटीआर 606 (कर) और सी.आई.टी. बनाम सुरेंद्र कुमार भदानी, (1987) 164 आईटीआर 323 (पैट), संदर्भित और निहित रूप से अनुमोदित।

3.1. जहां तक आकलन वर्ष 1957-58 से 1961-62 के लिए धारा/18 ए के तहत दंडात्मक ब्याज लगाने वाले आदेश की अपीलियता का सवाल है, इस मामले में, चूंकि दंडात्मक ब्याज धारा 18 ए(6) या 18 ए(8) के तहत लगाया गया था। मूल्यांकन आदेश में और मूल्यांकन आदेश के खिलाफ दायर अपील में इस पर आपत्ति जताई गई थी, निर्धारिती अपील में आपत्ति लेने का हकदार था। चूंकि उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों को उसके द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में नहीं निपटाया था, इसलिए मामले को विचार के लिए उच्च न्यायालय को भेज दिया गया है। [976-डी]

3.2. धारा 18 ए (6) या 18 ए (8) के तहत गणना और लगाए गए दंडात्मक ब्याज को कर निर्धारण के आदेश के खिलाफ निर्धारिती द्वारा दायर अपील में चुनौती दी जा सकती है और निर्धारिती दंडात्मक ब्याज के भुगतान के लिए अपनी देनदारी से इनकार करने का भी हकदार होगा।, अधिनियम की धारा 18 ए के तहत, कर निर्धारण के लिए अपनी देनदारी से इनकार करते हुए। आयकर अधिनियम, 1922 के तहत, ब्याज लगाने वाले आदेश के खिलाफ अपील का कोई विशेष अधिकार नहीं है। लेकिन यदि मूल्यांकन के आदेश के खिलाफ अपील की जाती है और मूल्यांकन आदेश द्वारा ही ब्याज लगाया जाता है, तो निर्धारिती ब्याज की अनिवार्यता के संबंध में सवाल उठा सकता है। [975-जी, 976-ए]

पं. देव शर्मा बनाम सी.आई.टी., (1953) 23 आईटीआर 226 (सभी); बोड्डू सीतारमास्वामी बनाम सी.आई.टी., (1955) 28 आईटीआर 156 (एपी); साउथ इंडिया फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सी.बी.डी. टी, (1968) 70 आईटीआर 863 (मैड); राष्ट्रीय उत्पाद बनाम सी.आई.टी., (1977) 108 आईटीआर 935 (कर); सी.आई. बनाम शर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी, (1975) 100 आईटीआर 603 (गुजरात); के.एस. स्टोर्स बनाम सी.आई.टी., (1976) 103 आईटीआर 505 (गौ); केशरदेव जी श्रीनिवास मोरारका बनाम सी.आई.टी., (1963) 48 आईटीआर 404 (जन्म), संदर्भित और निहित रूप से अनुमोदित।

4. इस सवाल के संबंध में कि क्या अपीलकर्ता कंपनी आयकर और रॉयल्टी के बदले राज्य सरकार को भुगतान की गई अतिरिक्त रॉयल्टी की राशि रुपये से अधिक जमा करने की हकदार थी। 1,50,000 आकलन वर्ष 1957-58 से 1960-61 के लिए अनुमेय कटौती थी, क्योंकि उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष सामग्री के आलोक में मामले की उचित

सराहना नहीं की थी, जिसमें शामिल थे अधिनियम की धारा/10(2)(xv) के प्रभाव के साथ-साथ पहले मूल्यांकन वर्षों के लिए अपीलकर्ता के स्वयं के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के कारण, मामले को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय में भेज दिया गया है। [976 -एफ, 978-ई, एच]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 685, 1980 आदि।

डी.बी.सी.आई.टी.आर. संख्या 24, 1979 में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 30.7.79 से।

आर. के. मेहता और अपीलकर्ता के लिए सुश्री मनिका मेहता।

प्रत्यर्थी के लिए एस.एन. टेरडोल के लिए एस. राजप्पा।

न्यायालय का फैसला सुनाया गया था।

परिपूर्णन, जे. - अपीलकर्ता एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसे पत्थर उत्खनन का व्यवसाय चलाने के लिए 17.1.1945 को तत्कालीन भारतीय राज्य कोटा में शामिल किया गया था। यह आयकर का निर्धारिती है। यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर खंडपीठ द्वारा दिनांक 26.11.1979 को दिए गए फिटनेस प्रमाण पत्र के अनुसरण में दायर की गई है, जो कि 1970 के आयकर संदर्भ संख्या 24 में दिनांक 30.7.1979 के फैसले और आदेश से उत्पन्न हुआ है। उक्त निर्णय (1981) 130 आईटीआर 868 [सीआईटी बनाम एसोसिएटेड स्टोन इंडस्ट्रीज (कोटा) लिमिटेड] में रिपोर्ट किया गया है। उच्च न्यायालय ने अपने सामान्य निर्णय दिनांक 30.7 में अपीलकर्ता पर 1950-51 से 1956-57 के वर्षों के लिए किए गए पुनर्मूल्यांकन की वैधता के साथ-साथ 1957-58 से 1961-62 के वर्षों के लिए किए गए आकलन की वैधता पर भी विचार किया। 1979 (1970 का आईटीआर नंबर 24)। वर्ष 1950-51 से 1956-57 के लिए पुनर्मूल्यांकन की वैधता और वैधता तय करने में कुछ पहलुओं का निर्णय निर्धारिती/अपीलकर्ता के पक्ष में किया गया था। मूल्यांकन वर्ष 1950-51 से 1961-62 के संबंध में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा किए गए एक समेकित संदर्भ पर, कानून के सात प्रश्न उच्च न्यायालय के निर्णय के लिए संदर्भित किए गए थे। इनमें से कानून के निम्नलिखित 5 प्रश्न, अर्थात् प्रश्न संख्या 1, 2, 5, 6 और 7, जिनका उत्तर निर्धारिती के विरुद्ध दिया गया था, अभी भी हमारे समक्ष अपील में हैं: -

1. क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, वर्ष 1950-51 से 1956-57 के लिए पुनर्मूल्यांकन, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 34(1)(ए) के तहत वैध रूप से किया गया था, 1922?
2. क्या, तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, राजस्व यह दावा करने का हकदार था कि वर्ष 1954-55, 1955-56 और 1956-57 के लिए पुनर्मूल्यांकन धारा 34(1)(बी) के तहत वैध रूप से किया गया था, अधिनियम?
3. क्या आकलन वर्ष 1957-58 से 1961-62 के लिए अधिनियम की धारा 18 ए के तहत दंडात्मक ब्याज लगाने वाले आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है ?
4. क्या निर्धारिती-कंपनी भुगतान की गई अतिरिक्त रॉयल्टी की राशि के क्रेडिट की हकदार थी, जिसे कंपनी के आयकर और सुपर-टैक्स देनदारी के बदले में माना जाता है?

5. क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, 2 मई को कोटा के महामहिम महाराव साहब की सरकार द्वारा दिए गए पट्टे के खंड 18 के तहत 1,50,000 रुपये से अधिक की रॉयल्टी का भुगतान किया गया था? 1945, जिसे जिला न्यायाधीश, कोटा द्वारा आयकर, सुपर-टैक्स आदि के बदले में माना गया है, निर्धारण वर्ष 1957-58 से 1960-61 में एक अनुमेय कटौती है?

2. इस स्तर पर, यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के मामले में विचार करने के लिए निर्धारिती ने उच्च न्यायालय के उसी फैसले के खिलाफ अत्यधिक सावधानी बरतते हुए, 1980 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 10840 दायर की है। दोषपूर्ण या अस्थिर पाया गया है। उक्त विशेष अनुमति याचिका पर अलग से गुण-दोष के आधार पर विचार करना अनावश्यक है।

3. हमने अधिवक्ता को सुना।

4. इस अपील में शामिल विवाद को तय करने के लिए प्रासंगिक तथ्य विवाद में नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में इन्हें सही ढंग से संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया है:

कोटा राज्य के तत्कालीन महाराव ने 2 मई, 1945 को अक्टूबर, 1944 से शुरू होने वाली 15 वर्षों की अवधि के लिए निर्धारिती-कंपनी को पट्टा प्रदान किया। निर्धारिती-कंपनी द्वारा कोटा के तत्कालीन महाराव के साथ किए गए पट्टा समझौते का खंड 18 फर्श के पत्थरों की खुदाई के लिए निम्नानुसार था:-

18.(i) अनुदानकर्ता द्वारा दी गई रियायतों और विशेषाधिकारों को ध्यान में रखते हुए और आयकर, सुपर-टैक्स और अतिरिक्त लाभ कर के बदले में, अनुदानकर्ता रुपये की दर से खोदे गए पत्थर पर अनुदानकर्ता को रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए अनुबंध करता है। प्रति 100 वर्ग फुट पर एक, प्रति वित्तीय वर्ष रु. 1,50,000 की न्यूनतम राशि के अधीन, बशर्ते कि प्रति 100 वर्ग फुट पर रु. 1 की उपरोक्त दर तब तक लागू रहेगी जब तक बिना पॉलिश की बिक्री दर रहेगी स्लैब रुपये से अधिक नहीं है। 10 प्रति 100 वर्ग फुट; बिक्री दर इस आंकड़े से ऊपर जाने की स्थिति में प्रति 100 वर्ग फुट रॉयल्टी दस रुपये से अधिक के 25% तक बढ़ा दी जाएगी।

(ii) न्यूनतम रॉयल्टी प्रत्येक तिमाही में चार समान किस्तों में अग्रिम रूप से देय होगी। बशर्ते कि यदि किसी तिमाही में उप-पैरा (i) में उल्लिखित चूहों पर देय रॉयल्टी की गणना उस तिमाही के लिए अग्रिम भुगतान की गई न्यूनतम रॉयल्टी की किस्त से अधिक हो, तो शेष राशि अगली तिमाही के भीतर बनाई जाएगी।

कोटा राज्य का संयुक्त राज्य राजस्थान में विलय हो गया और भारतीय आईटी अधिनियम, 1922, 1 अप्रैल, 1950 से नवगठित राजस्थान राज्य में लागू किया गया। निर्धारिती-कंपनी ने आय आयुक्त को एक आवेदन प्रस्तुत किया- इस घोषणा के लिए कर कि उसे कोटा के तत्कालीन महाराव द्वारा उसे दिए गए पट्टे की शर्तों के अनुसार आयकर के भुगतान से छूट दी गई थी। लेकिन उक्त आवेदन खारिज कर दिया गया। इसके बाद, निर्धारिती-कंपनी ने भारत संघ और राजस्थान राज्य के खिलाफ जिला न्यायाधीश, कोटा की अदालत में एक नागरिक मुकदमा दायर किया, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई कि उसे आयकर के भुगतान से छूट दी गई है और उसके द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी 1,50,000 की न्यूनतम राशि से अधिक की राशि आयकर, सुपर-टैक्स आदि के बदले में थी। 23 अगस्त, 1957 के अपने डिक्री और आदेश द्वारा विद्वान जिला न्यायाधीश ने माना

कि रॉयल्टी जो निर्धारिती-कंपनी द्वारा भुगतान की गई थी राजस्थान राज्य को, अनुदान के खंड 18 के प्रावधानों के अनुसार, दो भाग शामिल थे, अर्थात्, 1,50,000 रुपये की राशि उचित रॉयल्टी का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि रॉयल्टी की शेष राशि निर्धारिती-कंपनी द्वारा भुगतान की जाती थी। आयकर, सुपर-टैक्स और अतिरिक्त लाभ-टैक्स के बदले में था। विद्वान जिला न्यायाधीश के अनुसार, राजस्थान राज्य न्यूनतम रॉयल्टी रुपये का हकदार था। 1,50,000, क्योंकि उनके अनुसार, उक्त राशि सरकार द्वारा निर्धारिती-कंपनी को दी गई रियायतों और विशेषाधिकारों के कारण थी, जबकि निर्धारिती-कंपनी द्वारा भुगतान की गई शेष राशि 1,50,000 रुपये से अधिक थी। आयकर, सुपर-टैक्स और अतिरिक्त लाभ कर के बदले में भुगतान की गई राशि को दो भागों में विभाजित किया गया है, जो आय या मुनाफे पर संघीय करों के माध्यम से भारत संघ को देय था, जबकि शेष राशि अवशेष, सीएल के तहत निर्धारिती-कंपनी द्वारा भुगतान की गई राशि में से। आयकर, अधिकर एवं अतिरिक्त लाभ कर की कटौती के पश्चात अनुदान का 18 भाग राजस्थान राज्य को देय होगा। इस प्रकार, राजस्थान राज्य को न्यूनतम रॉयल्टी राशि रुपये का हकदार माना गया। 1,50,000 जबकि भारत संघ को उस वर्ष भुगतान की गई अतिरिक्त रॉयल्टी में से संघीय करों के संबंध में निर्धारिती-कंपनी की कर देनदारी के बराबर राशि का हकदार माना गया था, और राजस्थान राज्य शेष का हकदार था। अनुदान के सीएल.18 के तहत निर्धारिती-कंपनी द्वारा भुगतान की गई कुल राशि में से शेष। हालाँकि, विद्वान जिला न्यायाधीश ने भारत संघ के खिलाफ मुकदमे को खारिज कर दिया। विद्वान जिला न्यायाधीश, कोटा द्वारा पारित आदेश का जहां तक भारत संघ का संबंध है, बाध्यकारी प्रभाव नहीं था।

आयकर अधिकारी ने, 1950-51 से 1956-57 के वर्षों के आकलन में, निर्धारिती-कंपनी की कर योग्य आय से 1,50,000 रुपये की न्यूनतम रॉयल्टी राशि की कटौती को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि वह पूंजी थी। व्यय, जबकि निर्धारिती-कंपनी द्वारा 1,50,000 रुपये से अधिक भुगतान की गई रॉयल्टी की कटौती की अनुमति दी गई थी। आकलन वर्ष 1957-58 से 1961-62 के आकलन के संबंध में भी उनकी यही स्थिति कायम रही। वर्ष 1959 में, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 34(1) (ए) के तहत कर निर्धारण वर्ष 1950-51 से 1956-57 के लिए कर के पुनर्मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी किए गए थे। आईटीओ ने वर्ष 1950-51 से 1956-57 के लिए निर्धारिती-कंपनी की आय का पुनर्मूल्यांकन किया और माना कि निर्धारिती-कंपनी द्वारा 1,50,000 रुपये से अधिक का भुगतान की गई रॉयल्टी की राशि आय के बदले में थी। - कर इत्यादि, उसे निर्धारिती-कंपनी को कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जा सकती थी और इस प्रकार कटौती के रूप में पहले से अनुमत अतिरिक्त रॉयल्टी की राशि को अस्वीकार कर दिया गया था और निर्धारिती-कंपनी की आय में वापस जोड़ दिया गया था। निर्धारिती-कंपनी ने आईटीओ, कोटा द्वारा पारित पुनर्मूल्यांकन के उपरोक्त आदेशों के खिलाफ एएसी के समक्ष अपील की, लेकिन अपील खारिज कर दी गई। फिर निर्धारिती-कंपनी ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की, जिसने मूल्यांकन वर्ष 1950-51 से 1956-57 के लिए अधिनियम की धारा 34(1)(ए) के तहत की गई पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही से संबंधित सात अपीलों का निपटारा किया। 7 सितंबर, 1968 के एक समेकित आदेश द्वारा। ट्रिब्यूनल ने माना कि कलकत्ता डिस्काउंट कॉम में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। लिमिटेड बनाम आईटीओ [(1961) 41 आईटीआर 191]। ट्रिब्यूनल द्वारा यह माना गया कि निर्धारिती-कंपनी ने सभी प्रासंगिक या भौतिक तथ्यों का खुलासा किया था और चूंकि निर्धारिती -कंपनी की ओर से वर्षों के संबंध में मूल्यांकन के लिए आवश्यक किसी भी प्रासंगिक सामग्री का पूरी तरह से और सही मायने में खुलासा करने में कोई विफलता नहीं थी। प्रश्न,

अधिनियम की धारा 34(1)(ए) के तहत पुनर्मूल्यांकन के लिए क्षेत्राधिकार को लागू करने के लिए आवश्यक पूर्व-अपेक्षित शर्तें अनुपस्थित थीं। ट्रिब्यूनल ने आगे कहा कि मूल्यांकन वर्ष 1954-55, 1955-56 और 1956-57 के लिए पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही, हालांकि उन वर्षों के लिए मूल मूल्यांकन की तारीख से चार साल की अवधि के भीतर शुरू की गई थी, फिर भी क्योंकि ऐसी कार्यवाही शुरू की गई थी अधिनियम की धारा 34(1)(ए) के तहत, उन्हें धारा 34(1)(बी) के तहत बनाए जाने के रूप में बरकरार नहीं रखा जा सकता है। अधिनियम का. ट्रिब्यूनल ने यह भी माना कि निर्धारिती-कंपनी द्वारा राज्य सरकार को भुगतान की गई अतिरिक्त रॉयल्टी का हिस्सा, जो निर्धारिती-कंपनी की कर देयता के बराबर था, को आयकर और अन्य के रूप में अनुमेय कटौती के रूप में नहीं रखा जा सकता है। कर संघ सरकार को देय थे। हालांकि, अतिरिक्त रॉयल्टी का शेष भाग, जो निर्धारिती-कंपनी द्वारा कर देयता के बदले में भुगतान की गई राशि को अतिरिक्त रॉयल्टी में से घटाने के बाद अवशेष के रूप में बचा हुआ था, सिद्धांतों के आधार पर अनुमेय कटौती थी। गोटेन लाइम सिंडिकेट बनाम सीआईटी [(1966) 59 आईटीआर 718] में सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य द्वारा निर्धारित। ट्रिब्यूनल ने आगे कहा कि पॉलिश किए गए पत्थरों पर रॉयल्टी का भुगतान सीएल के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। समझौते के अनुच्छेद 19 में पत्थरों की लागत का एक हिस्सा शामिल है और यह राजस्व प्रकृति का व्यय होने के कारण एक अनुमेय कटौती है। ट्रिब्यूनल ने अंततः माना कि निर्धारिती-कंपनी रॉयल्टी के उस हिस्से के क्रेडिट की हकदार थी, जो उसने निर्धारिती-कंपनी के आयकर और सुपर-टैक्स देनदारी के बदले में भुगतान किया था।

7 सितंबर, 1968 को पारित एक अन्य आदेश द्वारा, ट्रिब्यूनल ने मूल्यांकन वर्ष 1957-58 से 1961-62 के संबंध में निर्धारिती-कंपनी द्वारा की गई अपीलों को यह मानते हुए अनुमति दी कि न्यूनतम राशि 1,50,000 रुपये है। इसके द्वारा देय रॉयल्टी, राजस्व प्रकृति का व्यय था और एक अनुमेय कटौती थी और निर्धारिती-कंपनी द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त रॉयल्टी में से, आयकर, सुपर-टैक्स, आदि के बराबर राशि के भुगतान के बाद बचा हुआ अवशेष था। ., संघ सरकार के लिए, राजस्व व्यय भी था और एक अनुमेय कटौती थी, हालांकि भारत संघ को देय आयकर, सुपर-टैक्स और अन्य प्रत्यक्ष करों के संबंध में अपनी देनदारी का प्रतिनिधित्व करने वाली अतिरिक्त रॉयल्टी की राशि से कटौती नहीं की जा सकती थी। निर्धारिती-कंपनी की कर योग्य आय, उसी दिन पारित पहले आदेश में दिए गए तर्क को अपनाते हुए, जिसे ऊपर संदर्भित किया गया है।

3. हम केवल प्रश्न संख्या 1, 2, 5, 6 और 7 के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उत्तरों से चिंतित हैं, जो निर्धारिती के खिलाफ हैं। प्रश्न संख्या 1 पर, उच्च न्यायालय ने माना कि वर्ष 1950-51 से 1956-57 के लिए पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही अधिनियम की धारा 34(1)(ए) के तहत वैध रूप से शुरू और संपन्न की गई थी। प्रश्न संख्या 2 पर, मूल्यांकन वर्ष 1954-55, 1955-56 और 1956-57 के संबंध में, उच्च न्यायालय ने वैकल्पिक याचिका पर पाया, कि उक्त वर्षों के लिए अपीलकर्ता-कंपनी के पुनर्मूल्यांकन को धारा 34 के तहत उचित ठहराया जा सकता है (1)(बी) अधिनियम का। प्रश्न संख्या 5 पर, उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 18 ए(6) या 18 ए(8) के तहत गणना और वसूले गए दंडात्मक ब्याज को केवल कर निर्धारण के आदेश के खिलाफ अपील में चुनौती दी जा सकती है और निर्धारिती इनकार करने का हकदार होगा। अधिनियम के तहत कर निर्धारण के अपने दायित्व से इनकार करते हुए दंडात्मक ब्याज के भुगतान के प्रति भी उसका दायित्व। यह इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश, मद्रास, कर्नाटक, गुजरात, गौहाटी और बॉम्बे उच्च न्यायालयों द्वारा व्यक्त विचार से भी सहमत है, जिसमें माना गया था कि दंडात्मक ब्याज लगाने के आदेश के खिलाफ कोई

अपील नहीं की जा सकती। मामले के तथ्यों पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू किए बिना, मामले को अस्पष्ट छोड़ दिया गया था। प्रश्न संख्या 6 पर, उच्च न्यायालय ने माना कि निर्धारिती-कंपनी अतिरिक्त रॉयल्टी की किसी भी राशि के लिए क्रेडिट प्राप्त करने की हकदार नहीं थी। प्रश्न संख्या 7 पर, यह माना गया कि व्यय राजस्व प्रकृति का नहीं होने के कारण प्रासंगिक मूल्यांकन वर्षों में अनुमेय कटौती नहीं हो सकती है।

4. हम उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर दिए गए कानून के उपरोक्त प्रश्नों (प्रश्न 1, 2, 5, 6 और 7) पर क्रमवार विचार करेंगे।

प्रश्न संख्या 1 आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 34(1) (ए) के तहत वर्ष 1950-51 से 1956-57 के लिए किए गए पुनर्मूल्यांकन की वैधता और वैधता से संबंधित है। धारा 34(1)(ए) अधिनियम के) और (बी) निम्नलिखित प्रभाव वाले हैं:

"34. मूल्यांकन से बचने वाली आय - (1) यदि - (ए) आयकर अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी निर्धारिती की ओर से धारा 22 के तहत अपनी आय का रिटर्न बनाने में चूक या विफलता के कारण और वर्ष के लिए या उस वर्ष के लिए उसके मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्यों को पूरी तरह से और सही मायने में प्रकट करने के लिए, आयकर के लिए प्रभार्य आय, लाभ या लाभ उस वर्ष के मूल्यांकन से बच गए हैं, या उनका कम मूल्यांकन किया गया है, या बहुत कम मूल्यांकन किया गया है। दर, या अधिनियम के तहत अत्यधिक राहत का विषय बना दिया गया है, या अत्यधिक हानि या मूल्यहास भत्ते की गणना की गई है, या

(बी) इसके बावजूद कि निर्धारिती की ओर से खंड (ए) में उल्लिखित कोई चूक या विफलता नहीं हुई है, आयकर अधिकारी के पास अपने कब्जे में जानकारी के परिणामस्वरूप यह मानने का कारण है कि आय, लाभ या लाभ प्रभार्य हैं किसी वर्ष के लिए आयकर निर्धारण से बच गए हैं, या इसके अंतर्गत रहे हैं- मूल्यांकन किया गया है, या बहुत कम दर पर मूल्यांकन किया गया है, या इस अधिनियम के तहत अत्यधिक राहत का विषय बनाया गया है, या अत्यधिक कम या मूल्यहास भत्ते की गणना की गई है।

वह खंड (ए) के अंतर्गत आने वाले मामलों में किसी भी समय और खंड (बी) के अंतर्गत आने वाले मामलों में उस वर्ष के अंत के चार वर्षों के भीतर किसी भी समय, निर्धारिती को नोटिस दे सकता है।

यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 34(1)(ए) के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए दो शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। (1) आयकर अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि आय मूल्यांकन से बच गई है, और (2) उसके पास यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि ऐसा पलायन करदाता की ओर से रिटर्न भरने में चूक या विफलता के कारण है। प्रासंगिक वर्ष के लिए उसके मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी भौतिक तथ्यों को पूरी तरह से और सही मायने में प्रकट करना। इस न्यायालय के निर्णयों से अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि निर्धारिती का कर्तव्य केवल सभी भौतिक तथ्यों को पूरी तरह और सही मायने में प्रकट करना है। अधिनियम की धारा 34(1)(ए) में निहित अभिव्यक्ति "भौतिक तथ्य" केवल प्राथमिक तथ्यों को संदर्भित करती है, और निर्धारिती का कर्तव्य ऐसे प्राथमिक तथ्यों का खुलासा करना है। निर्धारिती पर यह बताने या आयकर अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने का कोई कर्तव्य नहीं है कि प्रकट किए गए प्राथमिक तथ्यों से क्या तथ्यात्मक या कानूनी, या अन्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। (देखें -

कलकत्ता डिस्काउंट कंपनी लिमिटेड बनाम आईटीओ - 41 आईटीआर 191)। इस मामले में, अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने आदेश के पैराग्राफ 12 (पेपर बुक के पृष्ठ 321) में इस प्रकार पाया:

इस मामले में प्राथमिक तथ्य पट्टा समझौता और उसके नियम और शर्तें थीं। यह शुरू से ही आयकर अधिकारी के सामने था। वह जिला न्यायालय, कोटा के समक्ष लंबित निर्धारिती कंपनी, राजस्थान राज्य और केंद्र सरकार के बीच त्रिकोणीय विवाद से अवगत थे। उन्हें मूल्यांकन की कार्यवाही से दूर रहने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई थी। उन्होंने उक्त निषेधाज्ञा को संशोधित करा लिया था। इन परिस्थितियों में, निर्धारिती कंपनी के खिलाफ यह आरोप पूरी तरह से विफल हो जाता है कि उसने किसी भी भौतिक तथ्य को पूरी तरह से और सही मायने में प्रकट करने में चूक की थी या विफल रही थी। इसलिए, हमारी राय है कि आयकर अधिकारी के पास यह मानने के लिए कोई भी सामग्री नहीं थी कि करदाता-कंपनी की ओर से किसी भी प्रासंगिक सामग्री को पूरी तरह से और सही मायने में प्रकट करने में चूक या विफलता का कारण हो। अपील के तहत वर्षों के लिए इसके आकलन के लिए आवश्यक, आय मूल्यांकन से बच गई थी। दूसरे शब्दों में, हम मानते हैं कि धारा 34(1)(ए) के तहत क्षेत्राधिकार लागू करने के लिए आवश्यक भौतिक शर्त अनुपस्थित थी। इसलिए, हम मानते हैं कि धारा 34(1)(ए) के तहत पूरा किया गया पुनर्मूल्यांकन अधिकार क्षेत्र के बिना है और इसलिए रद्द किया जा सकता है।"

दूसरी ओर, उच्च न्यायालय ने यह कहकर मामले पर एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है कि आयकर अधिकारी अपीलकर्ता द्वारा दायर मुकदमे में एक पक्ष नहीं था, अदालत में दायर वाद की एक प्रति उसे सौंपी नहीं गई थी। और निर्धारिती-कंपनी दस्तावेज के विशेष भाग, अर्थात्, 2,5,1945 के पट्टा समझौते के खंड 18 और इस प्रकार आयोजित मामले के इस दृष्टिकोण में एक स्पष्ट संदर्भ देने के अपने कर्तव्य में विफल रही: -

" इस प्रकार, हम संतुष्ट हैं कि ट्रिब्यूनल यह मानने में सही नहीं था कि निर्धारिती-कंपनी सभी सामग्री प्रासंगिक या प्राथमिक तथ्यों का खुलासा करने में विफल नहीं हुई और केवल लीज समझौते का उत्पादन या त्रिकोणीय के बारे में आईटीओ की ओर से कुछ अस्पष्ट जागरूकता जिला न्यायाधीश, कोटा के समक्ष निर्धारिती, राजस्थान राज्य और भारत संघ के बीच विवाद और उस पर अंतरिम निषेधाज्ञा की तामील से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि आईटीओ को वास्तव में पता था कि भुगतान की गई राशि निर्धारिती-कंपनी द्वारा पट्टा समझौते के तहत न केवल उचित रॉयल्टी शामिल थी, बल्कि आयकर और अन्य करों के बदले में कुछ राशि का भुगतान भी किया गया था।"

इस दृष्टिकोण में, यह माना गया कि निर्धारिती-कंपनी सभी सामग्री या प्राथमिक तथ्यों का खुलासा करने में विफल रही और इसलिए 1922 अधिनियम की धारा 34(1)(ए) के तहत कार्यवाही शुरू की गई और समाप्त की गई। हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया दृष्टिकोण और निष्कर्ष निम्नलिखित कारणों से स्पष्ट रूप से गलत है।

5. इस मामले में प्राथमिक तथ्य अपीलकर्ता द्वारा कोटा राज्य के महाराव के साथ दिनांक 2.5.1945 को किया गया पट्टा समझौता है। इसे मूल मूल्यांकन के समय आयकर

अधिकारी के समक्ष रखा गया था। यह निर्धारिती का कर्तव्य नहीं है कि वह दस्तावेज के किसी विशेष खंड या हिस्से पर आयकर अधिकारी का ध्यान आकर्षित करे और उसे उससे कोई विशेष निष्कर्ष निकालने के लिए आमंत्रित करे। इसके अलावा, मुकदमे में भारत संघ और राजस्थान राज्य पक्षकार थे। निर्धारिती-कंपनी के खिलाफ किसी भी आयकर का आकलन करने या लगाने से अदालत द्वारा पारित अंतरिम निषेधाज्ञा, बाद के आदेशों द्वारा, भारत संघ द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर भिन्न थी। दरअसल, भारत संघ और आयकर आयुक्त ने मुकदमे में लिखित बयान दायर किए हैं। निषेधाज्ञा का आदेश आयकर अधिकारी की जानकारी में था, जैसा कि मूल आकलन से देखा जा सकता है। आयकर अधिकारी को जिला न्यायालय के समक्ष लंबित निर्धारिती-कंपनी, राजस्थान राज्य और भारत संघ के बीच त्रिकोणीय विवाद के बारे में पता था। इससे भी अधिक, आकलन के साथ आगे बढ़ने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा का आदेश आयकर अधिकारी को दिया गया था जिसे बाद में संशोधित किया गया था। इन मुख्य विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने यह मानने में पूरी तरह से गलती की कि अपीलकर्ता-कंपनी की ओर से संबंधित वर्षों के मूल्यांकन के लिए आवश्यक सामग्री या प्राथमिक तथ्यों को पूरी तरह और सही मायने में प्रकट करने में कोई चूक हुई थी। इसलिए, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्न संख्या 1 पर दिया गया उत्तर कि अधिनियम की धारा 34(1)(ए) के तहत शुरू की गई पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही 1950-57 के वर्षों के लिए वैध थी, कानून की दृष्टि से पूरी तरह से गलत है। हम उक्त निष्कर्ष को खारिज करते हैं और मानते हैं कि अधिनियम की धारा 34(1)(ए) के तहत मूल्यांकन वर्ष 1950-57 के लिए पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही अमान्य थी।

6. अब हम प्रश्न संख्या 2 पर विचार करेंगे कि क्या राजस्व वर्ष 1954-55, 1955-56 और 1956-57 के पुनर्मूल्यांकन को अधिनियम की धारा 34(1)(बी) के तहत वैधता के रूप में चुनौती दे सकता है या बचाव कर सकता है ?

उच्च न्यायालय ने प्रश्न संख्या 2 पर माना है कि उक्त तीन वर्षों के लिए अपीलकर्ता-कंपनी का पुनर्मूल्यांकन अधिनियम की धारा 34(1)(बी) के तहत उचित था। हमने फैसले के पहले भाग में देखा है कि अपीलकर्ता-निर्धारिती द्वारा भारत संघ और राजस्थान राज्य के खिलाफ जिला न्यायाधीश, कोटा की अदालत में एक नागरिक मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि उसे भुगतान से छूट दी गई है। आयकर और इसके द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी न्यूनतम राशि रुपये से अधिक है। 1,50,000/- आयकर, सुपर-टैक्स आदि के बदले में था। अनुदान के खंड 18 की व्याख्या करते हुए, जिला न्यायाधीश ने माना कि निर्धारिती द्वारा भुगतान की गई राशि में दो भाग शामिल थे, अर्थात् रुपये की राशि। 1,50,000/- उचित रॉयल्टी का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि शेष राशि, यानी, रुपये से अधिक भुगतान की गई राशि। 1,50,000/- आयकर, सुपर-टैक्स और अतिरिक्त लाभ कर के बदले में राशि का प्रतिनिधित्व करता है। राजस्थान राज्य को रुपये का हकदार माना गया। 1,50,000/- जो अपीलकर्ता-कंपनी को सरकार द्वारा दी गई रियायतों और विशेषाधिकारों के कारण था। रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया गया। 1,50,000/- को दो भागों में विभाजित किया गया था। एक भाग आयकर, सुपर टैक्स और अतिरिक्त लाभ कर के बदले भुगतान की गई राशि का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत संघ को देय था और कटौती के बाद अनुदान के खंड 18 के तहत निर्धारिती-कंपनी द्वारा भुगतान की गई राशि में से शेष राशि का प्रतिनिधित्व करता है। आयकर, सुपर टैक्स और अतिरिक्त लाभ कर राजस्थान राज्य को देय होगा। अवशेष का हकदार राजस्थान राज्य होगा। हालाँकि, जिला न्यायाधीश ने भारत संघ के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया। राजस्थान राज्य द्वारा दायर अपील में, यह माना गया कि दिनांक 2.5.1945 का समझौता

26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के लागू होने पर शून्य हो गया, निर्धारिती-कंपनी द्वारा भुगतान की गई राशि से अधिक न्यूनतम रु. इसमें 1,50,000/- रुपये रिफंडेबल थे। आयकर अधिकारी ने माना कि अपीलकर्ता-कंपनी द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी की राशि रुपये से अधिक है। 1,50,000/- आयकर, सुपर टैक्स और अतिरिक्त लाभ कर के बदले में होने के कारण कटौती की अनुमति नहीं दी जा सकती। पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही में, कटौती के रूप में पहले दी गई अतिरिक्त रॉयल्टी की राशि को अस्वीकार कर दिया गया और निर्धारिती-कंपनी की आय में वापस जोड़ दिया गया। अपीलीय सहायक आयुक्त के समक्ष अपीलकर्ता-निर्धारिती द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई। अपीलीय न्यायाधिकरण ने माना कि वर्ष 1950-51 से 1956-57 के लिए अधिनियम की धारा 34(1)(ए) के तहत कार्यवाही अमान्य है और वैकल्पिक रूप से वर्ष 1954-55, 1955-56 के लिए पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही अमान्य है। और 1956-57 हालांकि उन वर्षों के मूल मूल्यांकन की तारीख से चार साल की अवधि के भीतर शुरू किया गया था, लेकिन धारा 34(1)(बी) के तहत कायम नहीं रखा जा सका। अधिनियम की धारा 34 (10 (ए) के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। ट्रिब्यूनल ने यह भी माना कि निर्धारिती-कंपनी द्वारा राज्य सरकार को भुगतान की गई अतिरिक्त रॉयल्टी का हिस्सा जो कर देनदारी के बराबर था। निर्धारिती-कंपनी एक अनुमेय कटौती नहीं है क्योंकि कर केंद्र सरकार को देय थे। यह आगे माना गया कि हालांकि, अतिरिक्त रॉयल्टी का शेष हिस्सा जो अवशेष के रूप में छोड़ दिया गया था, बदले में भुगतान की गई राशि में कटौती के बाद निर्धारिती-कंपनी द्वारा कर देयता, (अतिरिक्त रॉयल्टी में से) अनुमेय कटौती थी। उच्च न्यायालय में यह विवादित नहीं था कि वर्ष 1954-55, 1955-56 और 1956-57 के लिए पुनर्मूल्यांकन एक अवधि के भीतर लिया गया था मूल मूल्यांकन कार्यवाही के पूरा होने की तारीख से चार साल की अवधि और इसलिए उन्हें अधिनियम की धारा 34(1)(बी) के तहत वैध रूप से किया जा सकता था। न ही उच्च न्यायालय के समक्ष कोई विवाद था कि रॉयल्टी की राशि का भुगतान किया गया था। और न्यूनतम रॉयल्टी राशि रु. 1,50,000/- का भुगतान आयकर, सुपर टैक्स और अतिरिक्त लाभ कर के बदले में किया गया था और जो राशि का भुगतान किया गया था, उस पर आयकर के भुगतान से छूट का दावा नहीं किया जा सकता है। यह निर्धारिती-कंपनी की आय थी और कर के दायरे में थी और जो वास्तव में, मूल मूल्यांकन के पूरा होने के समय मूल्यांकन से बच गई थी। मूल मूल्यांकन आदेश में, आयकर अधिकारी ने रॉयल्टी के माध्यम से निर्धारिती-कंपनी द्वारा भुगतान की गई पूरी राशि के लिए कटौती की अनुमति दी, जिसमें करों के बदले में भुगतान की गई राशि के साथ-साथ शेष राशि भी शामिल थी। उच्च न्यायालय ने उपरोक्त बायोडाटा पर माना कि आयकर अधिकारी के पास आय से बचने या आय के कम मूल्यांकन के संबंध में कुछ "जानकारी" थी और चूंकि मूल मूल्यांकन के चार वर्षों के भीतर कार्रवाई की गई थी, इसलिए ऐसी कार्रवाई को बरकरार रखा जा सकता है। अधिनियम की धारा 34(1)(बी) के तहत, भले ही कार्यवाही अधिनियम की धारा 34(1)(ए) के तहत शुरू की गई हो।

7. हमारा मानना है कि इस संबंध में उच्च न्यायालय का तर्क और निष्कर्ष कानूनन उचित है। अपीलकर्ता के वकील द्वारा इस संबंध में दो प्रकार की दलीलें दी गईं।

(1) पहली दलील यह थी कि अधिनियम की धारा 34(1)(ए) के तहत शुरू की गई कार्यवाही, जो मूल्यांकन वर्ष 1954-55, 1955-56 और 1956-57 के लिए अमान्य पाई गई थी, धारा के तहत कायम नहीं रखी जा सकती अधिनियम की धारा 34(1)(बी)। रघुबर दयाल राम किशन बनाम सीआईटी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर मजबूत निर्भरता रखी गई थी। (63 आईटीआर 572)।

(2) दूसरी दलील यह थी कि सिविल मामले में जिला न्यायाधीश, कोटा का निर्णय केवल लीज डीड पर आधारित था। लीज डीड के साथ-साथ जिला न्यायाधीश का निर्णय मूल मूल्यांकन के समय पहले से ही उपलब्ध था और इसे अधिनियम की धारा 34(1)(बी) को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नई सामग्री या जानकारी नहीं माना जा सकता है।

8. धारा 34 , खंड (ए) और (बी) पर एक नजर डालने से पता चलेगा कि उक्त खंड दो अलग-अलग स्थितियों से निपटते हैं। धारा 34 केवल एक मशीनरी धारा है। वे विभिन्न आकस्मिकताओं और स्थितियों को कवर करते हैं, लेकिन वे दो अलग-अलग और अलग-अलग न्यायक्षेत्रों से निपटते नहीं हैं। संपूर्ण धारा 34 -- खंड (ए) या खंड (बी) आय पलायन मूल्यांकन को फिर से खोलने के मामलों से संबंधित है। जबकि धारा 34(1)(ए) के लिए आयकर अधिकारी द्वारा एक विश्वास के गठन की आवश्यकता है, कि निर्धारिती की ओर से सभी भौतिक तथ्यों को पूरी तरह से और सही मायने में प्रकट करने में विफलता या चूक हुई है और बनाने के लिए कुछ सामग्री होनी चाहिए ऐसे तथ्य और ऐसी धारणा बनाने के लिए कुछ सामग्री होनी चाहिए कि निर्धारिती की ओर से विफलता या चूक के कारण निर्धारिती की आय बच गई है या उसका कम मूल्यांकन हुआ है, धारा 34(1)(बी) के लिए आवश्यक है कि भले ही निर्धारिती की ओर से कोई चूक या विफलता नहीं हुई हो, लेकिन आयकर अधिकारी के पास जानकारी है और वह यह विश्वास बना सकता है कि आय मूल्यांकन से बच गई है, वह चार साल की अवधि के भीतर ऐसा कर सकता है। धारा 34(1)(ए) के तहत शक्ति के प्रयोग की सीमाएं हैं , अर्थात्, आयकर अधिकारी उन कारणों को रिकॉर्ड करने के लिए बाध्य है, जिसके कारण विश्वास का निर्माण हुआ और केंद्रीय बोर्ड के आयुक्त की मंजूरी मिल गई। राजस्व की आवश्यकता है। धारा 34(1)(बी) मामलों के एक बड़े वर्ग को कवर करते हुए व्यापक महत्व की है। सामान्य नागरिक कार्रवाइयों में, यदि कोई पक्ष बड़ी राहत के लिए प्रार्थना करता है और न्यायालय मानता है कि वह इसका हकदार नहीं है, लेकिन साबित या स्वीकार किए गए तथ्यों से यह स्पष्ट है कि पक्ष कम राहत का हकदार है, तो यह हमेशा खुला रहता है उत्तरार्द्ध को अनुदान देने के लिए न्यायालय को। इसी प्रकार, यदि आयकर अधिकारी ने धारा 34(1)(ए) के कड़े और कठिन प्रावधानों के तहत कार्यवाही शुरू की है, जो अमान्य पाया जाता है, तो अपीलीय या अन्य उच्च प्राधिकारी को धारा 34(1)(बी) लागू करने से कोई नहीं रोक सकता है।) यदि खंड (बी) के आवेदन के लिए पूर्व-अपेक्षित शर्तें पूरी हो गई हैं। दूसरे शब्दों में, यदि धारा 34(1)(बी) की प्रयोज्यता की शर्तें जो केवल छोटी अवधि की सीमा प्रदान करती हैं, संतुष्ट हैं, तो धारा 34(1)(ए) के तहत शुरू किए गए मूल्यांकन को धारा 34 के तहत बरकरार रखा जा सकता है या उचित ठहराया जा सकता है। (1)(बी) अधिनियम के. इस पहलू पर, विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णय एक समान नहीं हैं। रघुबर दयाल राम किशन बनाम सीआईटी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय । (63 आईटीआर 572) ने माना है कि यह अनुमति योग्य नहीं है। दूसरी ओर, मृगांका मोहन सूर बनाम सीआईटी में कलकत्ता उच्च न्यायालय । (95 आईटीआर 503) ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय से असहमति व्यक्त की है कि आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 34(1) (ए) के तहत शुरू की गई पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही हालांकि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अलग कर दी गई है, फिर भी इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 34(1) (बी) के तहत बरकरार रखा गया है , बशर्ते कि रिकॉर्ड पर सामग्री पर, धारा 34(1)(बी) के तहत सभी आवश्यकताएं पूरी हों। निर्मला बिड़ला बनाम डब्ल्यूटीओ (105 आईटीआर 483-एफबी) में उसी उच्च न्यायालय ने अपने पहले के फैसले का पालन किया है। इसी तरह का प्रभाव गंगा सरन एंड संस बनाम आईटीओ मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय है । (130 आईटीआर 212)। राजबली हिरजी मेघानी बनाम एसएन सहाने (170 आईटीआर 614) में बॉम्बे हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने रद्द करने के लिए दायर रिट याचिका के

संदर्भ में गंगा सरन मामले (130 आईटीआर 212) में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से सहमति जताई है। आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी किए गए। अन्य निर्णय जो समान दृष्टिकोण रखते हैं वे हैं टीएम कौसाली बनाम छठा आईटीओ (155 आईटीआर 739), सीआईटी बनाम बनवारीलाल एंड संस (137 आईटीआर 91); मैसूर टोबैको कंपनी लिमिटेड। बनाम सीआईटी (157 आईटीआर 606) और सीआईटी बनाम सुरेंद्र कुमार भदानी (164 आईटीआर 323)।

9. दूसरी याचिका के संबंध में, अब यह काफी हद तक तय हो गया है कि आयकर अधिकारी द्वारा प्राप्त जानकारी को रिकॉर्ड के बाहर होने की आवश्यकता नहीं है; यह पहले से उपलब्ध मूल्यांकन रिकॉर्ड से प्राप्त किया जा सकता है। इस बिंदु पर कानून सलेम प्रोविडेंट फंड सोसाइटी लिमिटेड बनाम सीआईटी में निर्धारित किया गया है। (42 आईटीआर 547) और यूनाइटेड मर्केटाइल कंपनी लिमिटेड बनाम सीआईटी। (64 आईटीआर 218). इन निर्णयों को आनंदजी हरिदास एंड कंपनी बनाम एसपी कस्तुरे (एआईआर एससी 565) मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है। पृष्ठ 573 पर, न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

"सलेम प्रोविडेंट फंड सोसाइटी लिमिटेड में कॉमर्शियल टैक्स, मद्रास (1961) 42 आईटीआर 547 (एमएडी) में मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने धारा में पाए गए 'सूचना जो उसके कब्जे में आ गई है' शब्दों के दायरे की व्याख्या की। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 34, इस प्रकार देखी गई:

हम इस चरम प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि मूल्यांकन के रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जा सकता है जो स्वयं मूल्यांकन से बचने या कम मूल्यांकन को दर्शाता हो, उसे ऐसी जानकारी के रूप में देखा जा सकता है जिससे यह विश्वास हो कि मूल्यांकन से बच गया है या मूल्यांकन के तहत। मान लीजिए कि मूल्यांकन के मूल क्रम में कोई गलती आयकर अधिकारी द्वारा आगे की जांच के दौरान नहीं पाई जाती है, लेकिन इसे किसी अन्य निर्धारित या यहां तक कि एक अधीनस्थ या वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उसके ध्यान में लाया जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह जानकारी प्रकट की गई है। आयकर अधिकारी. यदि गलती स्वयं रिकॉर्ड के लिए असंगत नहीं है और मुखबिर ने रिकॉर्ड से जानकारी एकत्र की है, तो ऐसी परिस्थितियों में आयकर अधिकारी को जानकारी का तत्काल स्रोत एक अर्थ में रिकॉर्ड के लिए असंगत है। इस स्थिति को स्वीकार करना कठिन है कि रिकॉर्ड में जो कुछ दूसरे द्वारा देखा जाता है वह 'सूचना' है, जो आयकर अधिकारी स्वयं देखता है वह उसके लिए जानकारी नहीं है। बाद वाले मामले में वह सिर्फ खुद को सूचित करता है। यह धारा 34 के अर्थ में उसके कब्जे की जानकारी होगी। मूल्यांकन के रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट गलतियों के ऐसे मामलों में, वह रिकॉर्ड स्वयं जानकारी का एक स्रोत हो सकता है, यदि वह जानकारी किसी खोज या विश्वास की ओर ले जाती है कि मूल्यांकन से बच गया है या कम मूल्यांकन किया गया है। यूनाइटेड मर्केटाइल कंपनी लिमिटेड बनाम कॉमरेड मामले में केरल हाई की खंडपीठ के समक्ष "सूचना" शब्द का अर्थ फिर से विचार के लिए आया। इनकम टैक्स का केरल (1967) 64 आईटीआर 218 (केर)। उनके आधिपत्य का मानना था कि 'सूचित करने' का अर्थ है "ज्ञान प्रदान करना" और आयकर अधिकारी के समक्ष दायर किए गए कागजात में उपलब्ध कोई भी विवरण इसकी उपलब्धता मात्र से सूचना की वस्तु नहीं बन जाता है। यह उसके पास मौजूद सूचना की वस्तु में तभी रूपांतरित होता है जब इसके अस्तित्व का एहसास होता है और इसके निहितार्थ पहचाने जाते हैं।"

हमारा मानना है कि यद्यपि तीन वर्षों 1954-55, 1955-56 और 1956-57 की कार्यवाही को अधिनियम की धारा 34(1)(ए) के तहत कायम नहीं रखा जा सकता है, लेकिन उन्हें धारा 34(1)(के तहत कायम रखा जा सकता है या उचित ठहराया जा सकता है। बी) अधिनियम के, चूंकि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से पता चलता है कि धारा 34(1) (बी) के तहत पूरी की जाने वाली आवश्यक शर्तें पूरी हो गई हैं। हम बहुत सम्मान के साथ मानते हैं कि रघुबर दयाल राम किशन बनाम सीआईटी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला विपरीत था। (63 आईटीआर 572) अच्छा कानून नहीं है।

हमारा अगला संबंध प्रश्न संख्या 5 से है जो निर्धारण वर्ष 1957-58 से 1961-62 के लिए अधिनियम की धारा 18 ए के तहत दंडात्मक ब्याज लगाने वाले आदेश की अपीलियता से संबंधित है। उच्च न्यायालय ने प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर दिया है जिसमें कहा गया है कि धारा 18 ए(6) या 18 ए(8) के तहत गणना और लगाए गए दंडात्मक ब्याज को कर निर्धारण के आदेश के खिलाफ निर्धारिती द्वारा दायर अपील में चुनौती दी जा सकती है और निर्धारिती करेगा। अधिनियम की धारा 18 ए के तहत कर निर्धारण के लिए अपनी देनदारी से इनकार करते हुए दंडात्मक ब्याज के भुगतान के

976

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

[1997] 1 एस.सी.आर.

लिए अपनी देनदारी से इनकार करने का भी हकदार होगा। यह राय दी गई कि अधिनियम की धारा 18 ए(6) या 18 ए(8) के तहत ब्याज लगाने के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाएगी। उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए कानून पर आपत्ति नहीं की जा सकती। आयकर अधिनियम, 1922 के तहत ब्याज लगाने के आदेश के खिलाफ कोई विशेष अधिकार नहीं था। लेकिन, यदि मूल्यांकन के आदेश के खिलाफ अपील की जाती है और मूल्यांकन आदेश द्वारा ही ब्याज लगाया जाता है, तो निर्धारिती ब्याज की अनिवार्यता के संबंध में सवाल उठा सकता है। इस संबंध में, उच्च न्यायालय ने पं. में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किये गये विचार से सहमति व्यक्त की है। देव शर्मा बनाम सीआईटी 23 आईटीआर 226, बोड्डू सीतारामास्वामी बनाम सीआईटी (28 आईटीआर 156) में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, साउथ इंडिया फ्लोर मिल्स लिमिटेड बनाम सीबीडीटी (70 आईटीआर 863) में मद्रास उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय उत्पाद बनाम सीआईटी में कर्नाटक उच्च न्यायालय (108 आईटीआर 935), सीआईटी बनाम शर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी में गुजरात उच्च न्यायालय। (100 आईटीआर 603), केबी स्टोर्स बनाम सीआईटी में गौहाटी उच्च न्यायालय (103 आईटीआर 505) और केशरदेव श्रीनिवास मोरारका बनाम सीआईटी (48 आईटीआर 404) में बॉम्बे उच्च न्यायालय। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले में मूल्यांकन आदेश में धारा 18 ए(6) या (18 ए(8) के तहत दंडात्मक ब्याज लगाया गया था और मूल्यांकन के आदेश के खिलाफ दायर अपील में इस पर आपत्ति जताई गई थी। निर्धारिती इसे लेने का हकदार था। उक्त अपील में दंडात्मक ब्याज लगाने के संबंध में आपत्ति। उच्च न्यायालय ने इस मामले के तथ्यों को उसके द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में स्पष्ट रूप से नहीं निपटाया है और न ही यह बताया है कि निर्धारिती राहत का हकदार है या नहीं। तत्काल मामले में लागू कानून के संबंध में अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण से सहमति जताते हुए हम उच्च न्यायालय को तथ्यात्मक स्थिति और परिणामी आदेश का पता लगाने के बाद उचित आदेश पारित करने का निर्देश देते हैं जो कि निष्कर्ष को प्रभावी करने के लिए आवश्यक है। आ गया, पारित भी किया जा सकता है। उस उद्देश्य के लिए मामला उच्च न्यायालय को भेजा जाएगा।

10. हमारा अगला संबंध प्रश्न संख्या 6 और 7 से है – क्या अपीलकर्ता-कंपनी आयकर के बदले राज्य सरकार को भुगतान की गई अतिरिक्त रॉयल्टी की राशि, और सुपर टैक्स देनदारी और भी क्रेडिट करने की हकदार है। क्या रॉयल्टी का भुगतान रुपये से अधिक है। 2.5.1945 के लीज डीड के खंड 18 के तहत भुगतान किया गया 1,50,000/- निर्धारण वर्ष 1957-58 से 1960-61 के लिए अनुमेय कटौती है।

11. प्रश्न संख्या 6 का उत्तर देते हुए, उच्च न्यायालय ने माना है कि भुगतान की गई अतिरिक्त रॉयल्टी की राशि को अपीलकर्ता-कंपनी की कर देनदारी के संबंध में भारत संघ को भुगतान किया गया नहीं माना जा सकता है, क्योंकि कोई भी राशि नहीं दी गई थी। अपीलकर्ता-कंपनी द्वारा भारत संघ को भुगतान किया गया। यह भी माना गया कि राज्य सरकार को भुगतान की गई अतिरिक्त रॉयल्टी को भारत संघ की ओर से या उसके एजेंट के रूप में भुगतान नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यह माना गया कि निर्धारिती-कंपनी अतिरिक्त रॉयल्टी की किसी भी राशि के लिए क्रेडिट पाने की हकदार नहीं थी, जिसका भुगतान निर्धारिती-कंपनी द्वारा राज्य सरकार को किया गया था।

12. प्रश्न संख्या 7 का उत्तर देते हुए, उच्च न्यायालय ने माना कि अतिरिक्त रॉयल्टी में से प्रासंगिक वर्षों के लिए अपीलकर्ता-कंपनी की कर देनदारी के बराबर राशि, अनुमेय कटौती नहीं थी। अतिरिक्त रॉयल्टी का शेष भाग या अवशेष आर. 1,50,000/- की न्यूनतम रॉयल्टी के समान होगा और एक अनुमेय कटौती है। यह स्पष्ट कर दिया गया था कि करदाता-कंपनी की कर देनदारी के बराबर की राशि, अतिरिक्त रॉयल्टी में से, जिसे आयकर, सुपर टैक्स आदि के बदले में भुगतान किया गया है, अनुमेय कटौती नहीं है।

13. हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अनदेखी करते हुए उपरोक्त तरीके से प्रश्न संख्या 6 और 7 का उत्तर देने में गलती की, जिसमें भारत संघ और राज्य सरकार पक्षकार थे और उस संबंध में महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध थी। वकील ने इस प्रकार तर्क प्रस्तुत किये:

अतिरिक्त रॉयल्टी की राशि स्पष्ट रूप से निर्धारिती-कंपनी के आयकर और सुपर टैक्स देनदारी के भुगतान के लिए थी। उपरोक्त राशि भारत संघ की ओर से राजस्थान राज्य को भारत संघ की सहमति से और जिला न्यायाधीश, कोटा के दिनांक 18.02.1956 के आदेश के तहत न्यायालय को दिए गए एक उपक्रम के आधार पर प्राप्त हुई थी। ऐसी परिस्थितियों में, ट्रिब्यूनल ने सही माना था कि राज्य सरकार को किया गया भुगतान निर्धारिती-कंपनी द्वारा भारत संघ को उसकी कर देनदारी के लिए किया गया भुगतान था और आयकर अधिकारी को इसका श्रेय निर्धारिती को देने का सही निर्देश दिया था। – कंपनी। जिला न्यायाधीश, कोटा की अदालत ने सिविल सूट नंबर 17/53 में राजस्थान राज्य के खिलाफ और भारत संघ के पक्ष में 25 सितंबर, 1956 को इस आशय का एक डिक्री पारित किया कि चूंकि निर्धारिती-कंपनी ने पूरी रॉयल्टी का भुगतान कर दिया है और 1956-57 तक राजस्थान राज्य को अतिरिक्त रॉयल्टी, राज्य सरकार को निर्धारिती-कंपनी द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त रॉयल्टी में से आयकर, सुपर टैक्स इत्यादि की राशि का भुगतान भारत संघ को करना चाहिए, जिसका मूल्यांकन और मांग की गई है और जिसका निर्धारण वर्ष 1950-51 से 1958-

59 तक भारत संघ द्वारा निर्धारिती-कंपनी से आगे मूल्यांकन और मांग की जा सकती है। तदनुसार, जिला न्यायाधीश, कोटा ने रुपये के लिए एक डिक्री पारित की। निर्धारिती-कंपनी से लगाए गए और मांगे गए आयकर, सुपर टैक्स आदि के संबंध में किए जाने वाले भुगतान के लिए भारत संघ के पक्ष में और राजस्थान राज्य के विरुद्ध 23,99,474/- रु. इस डिक्री

का प्रभाव और प्रभाव उच्च न्यायालय की नजर से बच गया है। भारत संघ के पक्ष में एक सक्षम न्यायालय के पूर्वोक्त डिक्री के आलोक में यह माना जाएगा कि राजस्थान राज्य जिला न्यायालय के आदेशों के तहत और की सहमति से निर्धारिती-कंपनी द्वारा भुगतान किया गया धन रोक रहा था। आयकर अधिकारी की ओर से भारत संघ। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज करके और निर्धारिती-कंपनी के खिलाफ प्रश्न संख्या 6 का उत्तर देकर गलती की है। आयकर और सुपर टैक्स आदि के घटक सहित रॉयल्टी की पूरी राशि, 1953 के सिविल सूट नंबर 17 में अपने आदेश के तहत जिला न्यायाधीश, कोटा की अदालत में जमा की गई थी और जब पूरी राशि राज्य द्वारा वापस ले ली गई थी। राजस्थान जिला न्यायालय के आदेशों के तहत मुकदमे के अंतिम निर्णय के अधीन है और जब जिला न्यायाधीश की अदालत ने मुकदमे के निष्कर्ष पर राजस्थान राज्य को रुपये के भुगतान का आदेश दिया। प्रासंगिक मूल्यांकन वर्षों के लिए भारत संघ को उसकी आयकर मांग के संबंध में 23,99,474/- की राशि के मामले में, उच्च न्यायालय को यह मानना चाहिए था कि उपरोक्त राशि का भुगतान भारत संघ को किया गया था और निर्धारिती कंपनी इसके लिए हकदार थी। आयकर अधिकारियों से राशि का क्रेडिट। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(2)(xv) और न ही इस न्यायालय का पूर्व निर्णय अंतर-पक्षीय था (एसोसिएटेड स्टोन इंडस्ट्रीज (कोटा) लिमिटेड बनाम सीआईटी 82 आईटीआर 896) को इस संबंध में विज्ञापित किया गया। (82 आईटीआर 896 में बताया गया पिछला निर्णय निर्धारण वर्ष 1948-49 और 1949-50 से संबंधित था, जब कोटा राज्य में आयकर, सुपर-टैक्स आदि लगाने वाला कोई कानून नहीं था और इस न्यायालय ने माना था कि अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान आयकर, सुपर टैक्स आदि के बदले में नहीं किया जा सकता है, और यह एक अनुबंध की शर्तों पर भुगतान था। यह ध्यान में रखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण पहलू है।)

14. उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में उपरोक्त पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। यदि, वास्तव में, उपरोक्त सामग्री, ट्रिब्यूनल द्वारा उच्च न्यायालय को प्रस्तुत मामले के विवरण के साथ, उच्च न्यायालय के समक्ष उपलब्ध थी, तो हमें कहना चाहिए कि उच्च न्यायालय ने प्रश्न संख्या 6 और 7 पर विचार नहीं किया है। कानून के अनुसार. यह रिकॉर्ड से सत्यापन का मामला है और यह उच्च न्यायालय का काम है कि वह उपरोक्त पहलुओं पर अपना दिमाग लगाए और उचित निर्णय दे। हम आधार पर प्रश्न संख्या 6 और 7 का उत्तर देने से इनकार करते हैं। हालाँकि, हम ऊपर बताए गए तथ्यों के आलोक में प्रश्न संख्या 6 और 7 पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामला उच्च न्यायालय को भेजते हैं।

15. उपरोक्तानुसार अपील का निपटारा किया जाता है और इस निर्णय में निहित टिप्पणियों के आलोक में प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 के संबंध में विचार करने और उचित आदेश पारित करने के लिए मामला उच्च न्यायालय को भेजा जाता है। इस अपील में लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

बिना हर्जे।

अपील निस्तारित कि गई।

प्रमाणित किया जाता है कि यह मेरे (एकता मिश्रा, प्रथम अपर सीनियर सिविल जज, देहरादून) स्वयं द्वारा निर्णयों की शब्द दर शब्द की गयी जांच/सत्यापन हैं।